भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केंद्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

20 अगस्त 2022

गुजरात नरसंहार दंगई के बिलकिस बानो की मामले में दोषियो की रिहाई का निंदा करे!

सरकरि संस्था की भगवाकरण का विरोध करे!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी गुजरात दंगई के बिलकिस बानो की मामले में राज्य विभागो का दरूपयोग के सिलसिला को कठोर निंदा करती हैं। इस के साथ–साथ देश के हर एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशीलक और देश–प्रेमी जनता को सरकारी सस्थों की बढती भगवकरण के खिलाफ अपनी आवाज जागृत करन की आह्वान देती हैं। यह भगवाकरण का काल देश के जनता की मौलिक अधिकारों को गंभीर चोट प्रदान कर रहा हैं।

गुजरात की राज्य सरकार उन उम्रकैदी दोषी जो गुजरात नरसंहार दंगे के बिलकिस बानो की मामले में कारागार में वंदी थे, उनहे 15 अगस्त को रिहा किया गया। इसके जरिये देश की न्याय पद्वति और न्याय आदर्शो पर कलंक लग चुका है। बिलकिस बानो जब वह 5 महीने की गर्भवती थी तब नरसंहारी दंगइयो ने उन पर योन शोषण किया। और यही नही बिलकिस बानो अपनी 3 साल की मासूम बेटी को बड़ी क्रूरता से इन दंगाइये के हाथो मरते अपुनी आखो से देखा। यहा तक की बिलकिस बानो कें 14 परिवार सदस्य को मौत की घाट उतार दिया गया। बिलकिस बानो ने इंसाफ के लिए न्याय की दरवाजा पर दस्तक दी और इसके तहत सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2008 में उन सारे दोषीयों को उम्र कैद की सजा सुनायी थी। गुजरात सरकार का उन दोषीयो को माफ करने का निर्णय दोषीयों की रहम याचिका, जो उच्च न्यायालय में दर्ज किया गया था उस बुनियाद पर आधार हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन रहम याचिका को जांच करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने एक कमेटी की गठन की, और उसके निर्णय के तहत उन दोषयों को माफ करने का निर्णय लिया।

इस देश में अल्पसंख्याको और पीड़ित लोगों की परिस्थिति बिलकिस बानो की प्रतिक्रिया से समानता स्थापित करती हैं। और बिलकिस बानो ने यह कहा की ''इने दोषीयों की रिहाई होने पर, मेरे से मेरा अमन छीन लिया गया हैं। और मेरा न्याय व्यवास्था से विश्वास टूट पड़ा हैं''। यह दोषीयों और कोई नही, पर आरएसएस, वीहेचपी, भजरंग दल के सदस्य हैं। और मोदी–अमित षाह की गुट उन दोषीयों को रिहा इसलिए की हैं क्योंकी, मोदी – अमित शाह स्वयं ही इस हिंदुत्वा संस्था के महत्वपुर्ण सदस्य हैं। रमेश चंदन जोकी एक दोषी रिहा होने के बाद यह कहता हैं की ''जब तक गुजरात की सीआइड़ि मामले को देख रही थी, तब तक जांच सही दिशा पे चल रहा था''। यह साफ–साफ दिखाता हैं की, सरकार कैसे जोड़ तोड़ कर न्यायतंत्र को अपनी नियत्रण पर चला रहा हैं। यह दृश्य ब्राम्हणीय हिंदुत्व फासीवादी भाजपा शासन में गुजरात मोड़ल की फासीवादी नमूना दोहराता हैं।

राणा अयूब जो आपनी पत्रकारिता से गुजरात ड़ंगो की सच्चाई जनता कें सामने पेश किया और नरसंहार पर ''गुजरात फाइल्स'' नाम की पुस्तक कि रचना की, आज उस को न्याय पालिका से काले धन के मामले में सताया जा रहा हैं। पुलिस अफसर जैसे श्री कुमार और भठ, समाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाद जो गुजरात के दंगा पीड़ित मुसलमान जनता के साथ खड़े हुए, उन्हे जेलों के सालाको के पीछे बंद कर दिया गया हैं। यह निर्णय उस दिन लिया जाता हैं, जिस दिन झाफ्री के केस मे फैसला आया हुआ हैं। फिल्म निर्माता मुंबई के अविनाश दास को गिरफतार किया जाता है। इस पर आरोप है कि वह गृहमंत्रि अमित शाह की तस्वीर को गिरफतार आईएएस अफसर पूजा सिंघाल के साथ शेयर किया। यह साफ तौर से दिख रहा है की मोदी–अमित शाह की गुट सरकारी संस्था का गलत इस्तेमाल इस लिए किया जा रहा हैं कि, सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध आवाज ना खड़ा हो सके, और भाजपा अगले राष्ट्रीय चुनाव में दुबारा सत्ता में आ सके।

यह सभ गतिविधि कठोर भगवाकरण वास्तविकता को जो हर एक क्षेत्र में फैल रहा है, हमे साफ तौर से दिख रहा है। केंद्रीय कमेटी सारे उत्पीड़ित जनता, और उत्पीड़ित वर्गो, क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक संगठनों, मानवाधिकार संगठनों और देश के जनता को अपने कदम बढ़ाने और पूरी तीव्रता से यह खतरनाक काल का विरोध करने, और अपने प्यारे देश को बंधनमुक्त करने कि आह्वान देती है।

अभय
प्रवक्ता
केंद्रीय कमेटी